who can be a Lay Judge. A list of such Judges will be maintained. According to the State, at the district level, and the District Judge will provide Lay Judges to the court. This is just an idea as to how the court will be constituted. We can remove one or two of them if it is not beneficial to have the two Lay Judges. Like, we had 'jury' earlier in the trials. Now, it has been dispensed with. But in some parts of the world, jury is still continuing. So, in our system of Gram Nyayalayas, we want to have two Lay Judges only for the purpose of enabling the Judges to understand the local dialect because they will address directly to the people. It will be a participatory justice, justice at the doorsteps. So, this is how we are making this experiment on the basis of the 114th Report of Mr. Dhirubhai Desai, the then Chairman of the Law Commission.

शिक्षकों की नियुक्ति

*262. डा॰ कुमकुम राय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दस लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार कितनी नियुक्तियां की गई हैं; और

(ग) यदि अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं और उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जाएंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा पर गठित कार्यदल ने शिक्षा के प्रारंभिक स्तर के लिए 10.66 लाख शिक्षकों की अनुमानित आवश्यकता बताई थी।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत अब तक 4.92 लाख शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अक्तूबर, 2005 तक नियुक्त शिक्षकों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	53
2.	आंध्र प्रदेश	34676
3.	अरुणाचल प्रदेश	1206
4.	असम	7969

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अक्तूबर, 2005 तक नियुक्त शिक्षकों की संख्या
5.	बिहार	65650
6.	चंडीगढ़	240
7.	छत्तीसगढ़	28913
8.	दादरा और नगर हवेली	192
9.	दमन और दीव	0
10.	गोवा	0
11.	गुजरात	1662
12.	हरियाणा	4639
13.	हिमाचल प्रदेश	1911
14.	जम्मू और कश्मीर	15697
15.	झारखंड	31303
16.	कर्नाटक	10998
17.	लक्षद्वीप	3
18.	मध्य प्रदेश	49723
19.	महाराष्ट्र	1236
20.	मणिपुर	0
21.	मेघालय	4566
22.	मिजोरम	170
23.	उड़ीसा	35283
24.	पांडिचेरी	0
25.	पंजाब	1868
26.	राजस्थान	32894
27.	सिक्किम	191
28.	तमिलनाडु	8519
29.	त्रिपुरा	1629
30.	उत्तर प्रदेश	131394
31.	उत्तरांचल	3528
32.	पश्चिम बंगाल	16148
	कुलः	492261

Appointment of teachers

†262. SHRIMATI KUM KUM RAI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the target for appointment of ten lakh teachers for the students of class I to VIII was set in the Tenth Five Year Plan;

(b) if so, the appointments made so far, State-wise; and

(c) if no appointments have been made so far, the reasons therefor and by when the said appointments would be made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI): (a) The Working Group on Elementary and Adult Education constituted by the Planning Commission for the Tenth Five Year Plan had projected an estimated requirement of 10.66 lakh teachers for the elementary stage of education.

(b) Under the Sarva Shiksha Abhiyan Programme 4.92 lakh teachers have been appointed so far. State-wise details are at Statement (*See* below).

(c) Question does not arise.

Statement

Sl. No.	States/UTs	No. of teachers appointed under SSA upto Oct. 2005
1	2	3
1.	Andaman & Nicobar	53
2.	Andhra Pradesh	34676
3.	Arunachal Pradesh	1206
4.	Assam	7969
5.	Bihar	65650
6.	Chandigarh	240
7.	Chhattisgarh	28913
8.	Dadar & Nagar Haveli	192
9.	Daman & Diu	0

†Original notice of the question was received in Hindi.

1	2	3
10.	Goa	0
11.	Gujarat	1662
12.	Haryana	4639
13.	Himachal Pradesh	1911
14.	J & K	15697
15.	Jharkhand	31303
16.	Karnataka	10998
17.	Lakshadweep	3
18.	Madhya Pradesh	49723
19.	Maharashtra	1236
20.	Manipur	0
21.	Meghalaya	4566
22.	Mizoram	170
23.	Orissa	35283
24.	Pondicherry	0
25.	Punjab	1868
26.	Rajasthan	32894
27.	Sikkim	191
28.	Tamil Nadu	8519
29.	Tripura	1629
30.	Uttar Pradesh	131394
31.	Uttaranchal	3528
32.	West Bengal	16148
	TOTAL:	492261

डा॰ कुमकुम राय: उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में दसवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से 10 लाख 66 हजार शिक्षकों की अनुमानित आवश्यकता की बात बतायी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के तहत अब तक 4 लाख 92 हजार शिक्षक जो नियुक्त किए गए हैं, इन शिक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप क्या है? क्या ये शिक्षक स्थायी हैं या तदर्थ और इन्हें मिलने वाले वेतन और मानदेय तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, जहां तक सवाल पैदा होता है कि इनका मानदेय या उनकी सेलरी क्या है, यह सभी राज्य अपने हिसाब से तय करते हैं। जहां तक सवाल पैदा होता है कि उसमें रेग्युलर कितने हैं और बाकी टीचर्स कितने हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मुल्क के अंदर पैरा टीचर्स सिर्फ 8 प्रतिशत हैं और हर राज्य के अंदर जो सैलेरी का स्वरूप है, वह अलग-अलग है। पैरा टीचर्स या रेग्युलर टीचर्स की सैलेरी अलग-अलग होती है।

डा० कुमकुम राय: सर, मैं दूसरा पूरक प्रश्न यह पूछना चाहती हूं कि प्रश्न के जवाब में ही प्रौढ़ शिक्षा की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि प्रौढ़ शिक्षा अभी देश के कितने राज्यों में चलाई जा रही है और क्या प्रौढ़ शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षा मित्रों की तरह अलग से शिक्षकों की बहाली होगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो प्रौढ़ शिक्षा कौन लोग देंगे?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: इसके डीटेल्स मैं माननीय सदस्या के पास भिजवा दूंगा।

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, one of the important reasons for a large number of vacancies at the level of elementary school teachers is the reluctance on the part of those appointed to go to very distant villages which lack the basic facilities like accommodation, etc. I would like to know from the hon. Minister whether he is aware of a scheme that was being implemented in Madhya Pradesh, which I had an opportunity of watching for a few days, under which a person is selected from the village itself and, though he does not have the qualifications to be a regular teacher, he is given the training and appointed as a teacher. he takes classes from class one to class fifth and though there may be three or four students in each class, he would cater to the demand for teaching in that village and the neighbouring village. Mr. Digvijay Singh was the Chief Minister of Madhya Pradesh, at that time, and with his help I was able to visit a very few remote villages. Will the hon. Minister consider extending this scheme, which impressed me enormously, to areas which are located at very destant places and also to small hamlets which do not have the required number of children to have a formal school? Will the hon. Minister consider extending this scheme to these far off villages?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, जैसा कि मैंने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान या प्राइमरी और ऐलिमेंटरी जितने भी स्कूल हैं, इनको राज्य ही चलाता है और मध्य प्रदेश ने इस दिशा में कुछ कदम उठाया है। दूसरे राज्य भी अगर उस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन राज्यों की स्टडी करके, उनको देखकर, अगर अच्छी स्कीम है, तो राज्य उसको चला सकते हैं, इसमें भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Deputy Chairman, Sir, the Central Government must have given a target to each State as to how many teachers should be appointed during the Tenth Plan. Three years have completed and still we have not been able to achieve 50 per cent of the total target. I *would like to know from the hon. Minister which are the States which are* fulfilling the target and what is the highest percentage that they have achieved; which are the States which have not been able to fill up the vacancies at all and what are the reasons; how the Government is going to ensure that the target is met during the Tenth Plan; and, of course, after appointment, how the Government is going to ensure that they attend the classes regularly.

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, इन्होंने जो सवाल किया है, कुछ राज्यों में कोर्ट केस चल रहे थे, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल - यहां पर अपाइंटमेंट्स में कुछ ताखीर ज़रूर हुई है, लेकिन जैसे ही कोर्ट केस खत्म हो गए हैं, बड़ी तेजी से यहां पर अपाइंटमेंट्स हो रहे हैं। हमारा अपाइंटमेंट्स का जो टार्गेट था, 7.72 लाख का, उसमें 64 परसेंट हमने achieve कर लिया है। पिछले दिनों जो चुनाव हुए, कुछ स्टेट असेंबलीज़ के जैसे हरियाणा और बिहार में, उसकी वजह से और लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए झारखंड और उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से वहां पर कुछ डिले हुआ है, लेकिन जो टार्गेट है, जैसा कि सांसद महोदय ने कहा है, उसको हम लोग पूरा करवाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। जो टार्गेट है, उसको पूरा किया जाएगा।

DR. K. MALAISAMY: Sir, it has been stated that the estimated number of vacancies to be filled up are 10.66 lakh teachers. As against 10.66 lakh vacancies, they have appointed 4.92 lakh teachers. What is the time-frame to fill up all the remaining vacancies?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उपसभापति, जी वर्ष 2007 तक इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा।

श्री राजू परमार: उपसभापति जी, मंत्री महोदय ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीचर्स के appointment का state-wise और Union-Territory-wise जो ब्यौरा दिया है, उसके हिसाब से दमन और दीव में यह संख्या शून्य है, गोवा में शून्य है, मणिपुर में शून्य है, पांडिचेरी में शून्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे जो स्टेट्स हैं, जहां पर ज्यादा टीचर्स की जरूरत है, वहां पर उनका appointment क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उपसभापति जी, अभी कुछ राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। जिस स्टेट से भी जरूरत आ रही है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसमें कहीं पर भी कोई पक्षपात की बात नहीं है। जो भी डिमांड आती है और जहां भी जरूरत है, उसको हम लोग जरूर पूरा कर रहे हैं।

श्री लेखराज वचानी: उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में गुजरात सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती की योजना की शुरुआत की और 3 वर्षों में 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती हुई और सभी स्कूलों को हर क्लास के लिए टीचर्स मिल सके। इस स्कीम के तहत शुरुआत में सहायक शिक्षकों को 3 वर्ष के लिए 2,500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, 3 वर्षों तक उनकी कहीं भी बदली नहीं होगी और 3 वर्षों के बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। बाकी के प्रदेशों में जहां टीचर्स की जरूरत है, जहां 10 लाख टीचर्स की नियुक्ति होनी है, उनके लिए क्या माननीय मंत्री जी गुजरात के मॉडल पर ऐसी कोई स्कीम शुरू करना चाहते हैं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उपसभापति जी, गुजरात की एचीवमेंट बहुत अच्छी रही है, वहां पर स्कूलों में करीब 90 प्रतिशत टीचर्स हैं। इससे दूसरे राज्यों को सबक लेना चाहिए। जहां तक गुजरात मॉडल अपनाने की बात है या मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाने की बात है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जहां 100 परसेंट एचीवमेंट है, जो बीमार राज्य हैं, जहां पर मुश्किलें हैं, उनको इसे देखना चाहिए और इन्हें देखकर दूसरे राज्यों से अच्छी बातें सीखनी चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए। यह काम राज्यों को ही करना है।

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, this is a very ambitious scheme on education. Sir, Rs. 6,000 crores have been allocated for this scheme. The Centre has to give 75 per cent of it and the State has to contribute 25 per cent of the amount. some of the States, like Bihar and West Bengal, have not contributed anything. They have not appointed even a single teacher. Under this scheme, 32.40 lakh teachers were to be appointed in the year 2004-05 and in the year 2003-04, 29.67 lakh teachers were to be appointed. But these States have not contributed anything and have not appointed any teacher. What is the future plan of the Government so far as this scheme is concerned? Are they going to take any steps in this regard? Or, are they going to leave it as it is?

There are so many schools where children are there, but there are no teachers. Earlier, the position was, teachers used to be there but there were no children. What is the Government going to do in this regard? Is the Government going to take immediate action in this regard?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, उन्होंने दो राज्यों, वेस्ट बंगाल और बिहार का ज़िक्र किया है। बिहार के अन्दर 63 परसेंट टीचर्स का अप्वायंटमेंट हो चुका है। अभी वहां जो इलेक्शन हुए, उसकी वजह से बीच में रुकावट आई। जहां तक 75 और 25 परसेंट के शेयर का सवाल है, वह अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में भी कोर्ट केस था, वह अब खत्म हो गया है। मैं समझता हूं कि वहां भी अब तेजी से काम होगा। वहां भी स्टेट परसेंटेज की अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।

SHRI T. R. ZELIANG: Mr. Chairman, Sir, we are grateful to the Planning Commission for bringing out this target, and the achievement made by the Department is almost 50 per cent on ground. However, in the North-Eastern Region, we have eight States, out of which six States have been covered under this programme, excepting Nagaland and Manipur. I would like to know from the hon. Minister as to why these two States have not been covered under this programme. It it because that there are no proposals from these two States? Or, is there any other reason why Nagaland has not been covered under this programme?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, मैं इसकी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को दूंगा कि वहां पर यह अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है।

Students opting for Science and Technology

*263. SHRI R.K. ANAND:†
SHRI GIREESH KUMAR SANGHI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the percentage of students opting for Science and Technology had shown a sharp decline from 1950 to 2005;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) how it is comparable with the world figure; and

(d) the concrete measures to check this downslide?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No such data is maintained.

(d) Does not arise.

SHRI R.K. ANAND: Sir, I am surprised with the reply. I have got the UNDP Human Resources Development Report of 2001, which clearly indicates that India's much valued pool of trained scientists and technical personnel have already begun to shrink. I would like to know from the hon. Minister whether it is correct that 20 per cent of the seats of all engineering courses in the country remain vacant. If it is so, what steps are being taken to enable students to pursue higher education in science and technology?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri R. K. Anand.